Daily Current Affairs

Date : 22 January, 2026

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक (21 जनवरी, 2026)
2.	राजस्थान में 'गिव अप अभियान' की स्थिति
3.	PM कुसुम योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवॉर्ड
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र : कोटा 2. RFSDL तथा मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य MoU 3. साहित्य शिवालिक सम्मान – 2025 4. क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' : ब्यावर
5.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) : स्थापना दिवस
6.	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC)
7.	डिएगो गार्सिया
8.	अटल पेंशन योजना
9.	एक स्टेशन एक उत्पाद योजना (OSOP)
10.	रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट, 2026
11.	मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक (21 जनवरी, 2026)

चर्चा में क्यों?

- 21 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई।

मुख्य बिन्दु:

- इस बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की सम्पतियों एवं किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने, एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026:

- दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा से अशांति की परिस्थिति उत्पन्न होने पर क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा।
- विधेयक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।
- विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होगा तथा 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान है।
- विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थाई निवासियों की सम्पत्तियों एवं उक्त सम्पत्तियों पर किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी (अनुमोदन)

- **उद्देश्य :** प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का महत्त्वपूर्ण हब बनाना।
- इस पॉलिसी के तहत MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- इस नीति के अंतर्गत एयरोस्पेस एवं डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उपकरण एवं घटक निर्माता, सप्लायर एवं प्रिसीजन इंजीनियरिंग यूनिट
- MRO (मेंटेनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग) इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।

निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण:-

विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) :

- ₹50–300 करोड़ – लार्ज।
- ₹300–1000 करोड़ – मेगा।
- ₹1000 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

सेवा क्षेत्र (Service Sector) :-

- ₹25–100 करोड़ – लार्ज।
- ₹100–250 करोड़ – मेगा।
- ₹250 करोड़ से अधिक - अल्ट्रा मेगा।

प्रमुख प्रोत्साहन (Incentives) : -

- **एसेट क्रिएशन इंसेंटिव :** 7 वर्ष तक राज्य कर का 75 प्रतिशत पुनर्भरण।
- रीको से भूमि लेने वाले मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यमों को 10 वर्षों तक फ्लेक्जिबल लैण्ड पेमेंट और 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस हेतु लीज रेन्टल सब्सिडी का लाभ देय होगा।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- नीति में बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, ऑफिस-स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी जैसे प्रावधान तथा कैप्टिव पावर प्लांट में किए गए निवेश का 51 प्रतिशत पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल करने जैसे विशेष इन्सेंटिव्स का भी प्रावधान किया गया है।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी - 2025 (स्वीकृति)

- **'राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी' :** राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति।
- **उद्देश्य :** सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाना।
- साथ ही, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना तथा फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।
- पॉलिसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन, रिसर्च एवं डवलपमेंट तथा टैक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पार्कों में अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण और सर्कुलर पहलों के माध्यम से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- नीति में सात वर्षों तक विद्युत शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।
- 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
- कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राजस्थान में 'गिव अप अभियान' की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में 'गिव अप अभियान' की शुरुआत 1 नवम्बर, 2024 को हुई। इस अभियान के माध्यम से प्रदेशभर में जनवरी, 2026 तक 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है।

मुख्य बिन्दु:

- **नए नाम जोड़ने वाले शीर्ष तीन जिले :** जयपुर जिले में सर्वाधिक 3.17 लाख वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।
- **दूसरा स्थान :** बाड़मेर (3.07 लाख)
- **तीसरा स्थान :** सीकर (3.04 लाख)
- राज्य में वर्तमान में 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है।
- नए लाभार्थी जोड़ने की प्रक्रिया को सरल करते हुए ज़िला कलक्टर को NFSA में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने हेतु अधिकृत किया गया है।
- **तीन जिलों में अनाज ATM :** राज्य सरकार द्वारा जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर में अनाज ATM की स्थापना की जाएगी, जहाँ से खाद्य सुरक्षा लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानों पर स्वत: ही राशन प्राप्त कर सकेंगे।
- **नोट :** नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013) को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित 25 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 :

- खाद्यान्न की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना के रूप में वर्ष 2013 में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' के द्वारा देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई।

NFSA के तहत निम्नलिखित माध्यमों से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है:

- **अंत्योदय अन्न योजना :** यह सबसे गरीब आबादी को कवर करती है। इसके तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।
- **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

PM कुसुम योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान डिस्कॉम्स को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना) के कम्पोनेंट-सी में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **पुरस्कार प्रदानकर्ता :** केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में।
- **पुरस्कार प्राप्तकर्ता :** राजस्थान डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा।
- जनवरी, 2026 तक राज्य में कम्पोनेन्ट-ए एवं कम्पोनेन्ट-सी में 2877 मेगावॉट के कुल 1307 विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में राजस्थान डिस्कॉम्स देश में अग्रणी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 2333 मेगावॉट क्षमता के 899 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।
- **नोडल विभाग :** ऊर्जा विभाग को राज्य में इस योजना के नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है।

पीएम कुसुम:

- **शुरुआत :** मार्च, 2019
- **नोडल मंत्रालय :** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य :** किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना।

योजना के तीन घटक (Components):

कम्पोनेन्ट-ए:

- 500 किलोवाट (kW) से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले व्यक्तिगत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना।
- ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचित सब-स्टेशनों के पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना।
- उत्पादित विद्युत की खरीद स्थानीय डिस्कॉम (Distribution Company) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर की जाती है।
- **नोट :** राजस्थान में कंपोनेंट-ए का कार्यान्वयन प्रारंभ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) द्वारा किया जा रहा था, जिसे 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया गया।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

कम्पोनेन्ट-बी:

- 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना।
- इस घटक के तहत 3 से 10 हॉर्सपावर (HP) तक के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7.5 हॉर्सपावर तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है।
- जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाता है।
- 40 प्रतिशत में से किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।
- योजना के कम्पोनेंट-बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

कम्पोनेन्ट-सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन)

- नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 दिसम्बर, 2020 को पीएम-कुसुम योजना के घटक C के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो एक या एक से अधिक अलग-अलग कृषि फीडरों की वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपेक्स मोड या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।
- मंत्रालय ने 4,00,000 पम्प सेटों का सोलराईजेशन करने का लक्ष्य स्वीकृत किया है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र : कोटा** ■ राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा ₹71.22 करोड़ की लागत से कोटा में अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ■ कोटा में स्थापित इस प्लांट की क्षमता 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन होगी। ■ **सहयोगी संस्थान :** जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) ■ **राजस्थान में संचालित 7 अन्य पशु आहार संयंत्र :** कालाडेरा (जयपुर), पाली, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और लम्बियाकलाँ (भीलवाड़ा)।
2.	**RFSDL तथा मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य MoU** ■ हाल ही में, राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड (RFSDL) और मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। ■ इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए तकनीक आधारित सैलेरी लिंक्ड एडवांस कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
3.	**साहित्य शिवालिक सम्मान - 2025** ■ हाल ही में, जयपुर के वरिष्ठ कवि कन्हैयालाल भ्रमर को साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए 'साहित्य शिवालिक सम्मान-2025' से सम्मानित किया गया। ■ यह पुरस्कार देहरादून के लेखक गाँव में 23-25 दिसम्बर, 2025 को आयोजित 'अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव' में प्रदान किया गया। ■ **आयोजक :** अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, हरिद्वार।
4.	**क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' : ब्यावर** ■ केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा हाल ही में ब्यावर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया गया।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) : स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

- 19 जनवरी, 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का 21वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **NDRF की स्थापना :** 19 जनवरी, 2006 (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत्)
- **स्थापना का कारण:** वर्ष 1999 में ओडिशा सुपर साइक्लोन और वर्ष 2004 की सुनामी ने NDRF की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **मुख्यालय :** नई दिल्ली
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)
- **ध्येय वाक्य:** 'आपदा सेवा सदैव सर्वत्र"

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

संरचना:

- **नेतृत्व :** महानिदेशक (DG) ; वर्तमान NDRF महानिदेशक; पीयूष आनंद
- **बटालियन :** 16 बटालियन + 18 सर्च और रेस्क्यू टीमें कार्यरत।
- **NDRF अकादमी (वर्ष 2018) :** सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान।
- **कार्य:** NDRF को सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं जैसे ; बाढ़, CBRN (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु), पर्वतीय, चिकित्सा प्राथमिक प्रतिक्रिया और पशु बचाव तथा वर्ष 2022 में शामिल अग्नि प्रतिक्रिया में राहत व बचाव हेतु अधिकृत किया गया है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **स्थानीय राहत :** वायनाड भूस्खलन और उत्तराखंड की सिल्क्यारा सुरंग (वर्ष 2023) में रेस्क्यू ऑपरेशन में निर्णायक भूमिका।
- **अंतरराष्ट्रीय मिशन :** जापान ट्रिपल डिजास्टर (वर्ष 2011), नेपाल भूकंप (वर्ष 2015) तुर्कीए भूकंप (वर्ष 2023; ऑपरेशन दोस्त) तथा वर्ष 2025 में म्यांमार भूकंप में भूमिका।
- **NOTE:** उभरते जोखिमों को पहचानते हुए NDRF ने वर्ष 2024 को "CBRN तैयारी का वर्ष" घोषित किया।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC)

चर्चा में क्यों?

- 23 जनवरी, 2026 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।

United Nations
Economic and Social
Council (ECOSOC)

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीति के समन्वय, क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है।
- **स्थापना:** 23 जनवरी, 1946, लंदन (संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945 के तहत्)।
- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क, अमेरिका
- **सदस्य:** 54 देश (महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुना जाता है)
- **उद्देश्य :** आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करके सतत् विकास को आगे बढ़ाना ताकि कोई भी पीछे न छुटे।
- **परिषद के निर्णय:** निर्णय साधारण बहुमत से।
- **कार्य:** नीति समन्वय, संस्थागत संपर्क, SDG अनुवर्ती कार्यवाही तथा समावेशी सहभागिता को बढ़ावा देना।
- **NOTE :** यह परिषद्, यूनिसेफ, UNDP और UNHCR जैसी एजेंसियों के कार्यकारी बोर्डों का चुनाव करता है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

डिएगो गार्सिया

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डिएगो गार्सिया को लेकर चिंता जताई है। यह मामला यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिएगो गार्सिया को मॉरीशस को लौटाने से जुड़ा है।

मुख्य बिन्दु:

- डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डा मौजूद है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अवस्थिति:

- **मध्य हिन्द महासागर**
- **चागोस द्वीप समूह का हिस्सा**
- **प्रवाल द्वीप**

इतिहास:-

- **1965 ई. से चागोस द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में था।**
- **मई-2025 में यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत् पूरा चागोस द्वीप समूह मॉरीशस की संप्रभुता में माना गया। हालांकि डिएगो गार्सिया को यूनाइटेड किंगडम ने 99 साल की लीज पर ले रखा है।**
- **सैन्य महत्त्व:- डिएगो गार्सिया पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है।**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

अटल पेंशन योजना

चर्चा में क्यों?

- 21 जनवरी, 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों और अंतर-निधि के लिए वित्तीय सहायता के लिए विस्तार को स्वीकृती प्रदान की।

मुख्य बिन्दु:

- **कार्यान्वयन रणनीति :** यह योजना वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और सरकार निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करेंगी:
  1. असंगठित श्रमिकों के मध्य पहुँच बढ़ाने के लिए प्रचार और विकासात्मक गतिविधियां, जिनमें जागरूकता और क्षमता निर्माण शामिल है।
  2. योजना की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक धनराशि का आंवटन।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

प्रमुख प्रभाव:

- यह लाखों निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और भारत के पेंशन-आधारित समाज में परिवर्तन का समर्थन करता है।
- सतत् सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है।

पृष्ठभूमि: केंद्रीय क्षेत्रक योजना:

- **शुभारंभ:** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से APY को 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था।
- **मंत्रालय :** वित्त मंत्रालय।
- **आयु सीमा :** 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल।
- **योजना की विशेषताएँ:** APY 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर, अंशदान के आधार पर, प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है।
- **प्रगति:** 19 जनवरी, 2026 तक 866 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके है।
- **नोडल एजेंसी :** पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा।
- **विस्तार की आवश्यकता :** योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए निरंतर सरकारी समर्थन आवश्यक है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

एक स्टेशन एक उत्पाद योजना (OSOP)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अब 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक फैल चुकी है।

मुख्य बिन्दु:

OSOP :- अतिरिक्त जानकारी

- **शुरुआत:** वर्ष 2022
- **नोडल मंत्रालय:** रेल मंत्रालय
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत के स्थानीय और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना है। रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों को दिखाने और बेचने की जगह उपलब्ध करवाई जाती है।
- **शामिल उत्पाद:** आदिवासी समुदायों के हस्तशिल्प, स्थानीय बुनकरों के हथकरघा उत्पाद, लकड़ी की नक्काशी जैसे हस्तशिल्प, चिकनकारी और जरी-जरदोजी का काम, प्रसंस्कृत और अर्द्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
- यह योजना वोकल फॉर लोकल अभियान का हिस्सा है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को भी मजबूत करती है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट, 2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट, 2026 में वर्ष 2015 के लिए वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **रोजगार :** वर्ष 2015 से 2025 के मध्य अत्यधिक कामकाजी गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है (3.1% अंक तक)
- कम आय वाले देशों में वर्ष 2025 में 68% श्रमिक अत्यधिक या मध्यम गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे।
- **बेरोजगारी:** वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2025 में 4.9% पर बनी रही है तथा 408 मिलियन रोजगार का अंतर पैदा हुआ है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **रोजगार वृद्धि:**

उच्च आय वाले देश	गिरावट
मध्यम आय वाले देश	धीमी वृद्धि (0.5%)
निम्न आय वाले देश	वृद्धि तेज (3.1%)

रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन:

- पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्रों में श्रमिकों के स्थानान्तरण की गति आधी हो गई है।
- उत्पादक क्षेत्रों में यह धीमी गति से हो रहें परिवर्तन के कारण ही रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता वृद्धि कमजोर है।

लिंग और युवा असमानता:

- वैश्विक रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 2/5 हिस्से की है।
- महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी पुरुषों की तुलना में 24.2% अंक कम है।
- वैश्विक युवा बेरोजगारी दर वर्ष 2025 में बढ़कर 12.4% हो गई है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने से उच्च कौशल वाले प्रवेश स्तर के रोजगारों में शिक्षित युवाओं के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
- **अनौपचारिकता दर:** वैश्विक अनौपचारिकता दर में 0.3% की वृद्धि हुई (2015-2025 तक) और वर्ष 2026 तक 2.1 अरब श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत रहने का अनुमान है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट का आंकलन :

- **आर्थिक विकास:** भारत, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में' एक है; अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में उच्च GDP वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेंगी।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **विनिर्माण:** चीन (27%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (17%) की तुलना में वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी (3%) अत्यधिक कम है।

हरित अर्थव्यवस्था:

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।
- **हरित क्षेत्र:** भारत और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, हरित प्रतिभा की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

इतिहास

मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

- 21 जनवरी को प्रतिवर्ष मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का स्थापना दिवस (54वीं वर्षगाँठ) मनाया जाता है।

मुख्य बिन्दु:

मणिपुर का विलय :

- **वर्ष 1947 से पूर्व :** एक स्वतंत्र रियासत।
- **वर्ष 1947 :** महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ 'परिग्रहण के साधन (IOF)' पर हस्ताक्षर किए; भारत में विलय पर सहमति।
- **वर्ष 1948 :** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव।
- **वर्ष 1949 :** भारत सरकार के दबाव में भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विलय के बाद मणिपुर विधानसभा भंग कर C श्रेणी का राज्य बनाया गया।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **1 नवंबर, 1956:** मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र परिषद् अधिनियम, 1956 के तहत् एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- **21 जनवरी, 1972 :** पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (NEA-A) के माध्यम से मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

त्रिपुरा का विलय :

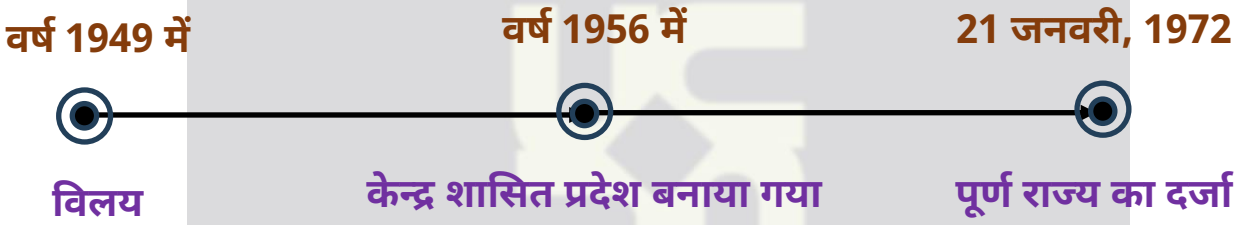

- वर्ष 1949 में त्रिपुरा को भारत में विलय की अनुमति रानी कंचन प्रभा देवी ने दी जिन्होंने राजा बीर बिक्रम की मृत्यु के बाद शासन सँभाला था।
- भारत में विलय के बाद त्रिपुरा C श्रेणी का राज्य बन गया।
- त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा NEA-R अधिनियम, 1971 के माध्यम से 1जनवरी, 1972 को प्रदान किया गया था।

मेघालय :

- **पृष्ठभूमि :** असम राज्य में खासी, गारो और जयन्तिया हिल्स के समुदायों द्वारा अधिक स्वायत्ता की माँग की गई।
- **वर्ष 1969 :** असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम द्वारा मेघालय को असम के अन्दर एक स्वायत्तता राज्य की स्थापना की गई।
- **वर्ष 1971 :** NEA-A अधिनियम, 1971 के तहत् मेघालय को भारत के 21वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR